आयुक्त का कार्यालय केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, अहमवाबाद उत्तर. सीआपरयू / CRU 1 9 MAR 2024 645 आवक रजिस्टर क्रमांक.

अमत महात्सव



आयुक्त का कार्यालय Office of the Commissioner केंद्रीय जीएसटी, अपील अहमदाबाद आयुक्तालय Central GST, Appeals Ahmedabad Commissionerate जीएसटी भवन, राजस्व मार्ग, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380015 GST Bhavan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 Phone: 079-26305065 - Fax: 079-26305136 E-Mail : <u>commrappl1-cexamd@nic.in</u> Website : <u>www.cgstappealahmedabad.gov.in</u>

## By SPEED POST

DIN	I:- 20240264SW00008181E4		
(क)	फ़ाइल संख्या / File No.	GAPPL/COM/STP/4045/2023 2333	
(ख)	अपील आदेश संख्याऔर दिनांक / Order-In –Appeal and date	AHM-EXCUS-002-APP-225/23-24 and 09.02.2024	
(ग)	पारित किया गया / Passed By	श्री ज्ञानचंद जैन, आयुक्त (अपील) Shri Gyan Chand Jain, Commissioner (Appeals)	
(घ)	जारी करने की दिनांक / Date of Issue	13.02.2024	
(ङ)	ArisingoutofOrder-In-OriginalNo.GST-06/D-VI/O&A/703/KHUSHI/AM/2022-23dated10.3.2023passedbyTheAssistant Commissioner, CGST Division-VI, Ahmedabad North		
(च)	अपीलकर्ता का नाम और पता / Name and Address of the Appellant Khushi Associates 4, SF-1, 2nd Floor, Jaymadi Shanti Smruti Complex B/s Little Wings BRTS Bus Stand Bopal, Ahmedabad - 380058		

कोई व्यक्ति इस अपील-आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि ऐसे आदेश के विरुद्ध हो सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way.

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन:-

## **Revision application to Government of India:**

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूवोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली: 110001 को की जानी चाहिए :-

A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid : -

(क) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानिकार खाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार मे हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलें में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है। In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

(घ) अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं 2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतरमूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ का मुख्य शीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(3) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम होतो रूपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्नरकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(2) उक्तलिखित परिच्छेद में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में 2<sup>nd</sup> माला, बहुमाली भवन, असरवा, गिरधरनागर, अहमदाबाद-380004।

To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at 2<sup>nd</sup>floor, Bahumali Bhawan, Asarwa, Girdhar Nagar, Ahmedabad: 380004. In case of appeals other than as mentioned above para.

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

2

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संषोधित की अनुसूची -1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूलआदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रतिपर रू 6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) एके प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्यमांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अंतर्गत, शामिल होगा कर्तव्य की मांग (Duty Demanded)।

(1) खंड (Section) 11D के तहत निर्धारित राशि;

- (2) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशिय;
- (3) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि।

यह पूर्व जमा ' लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना मेंए अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994).

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

(6) (i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute.



## ORDER-IN-APPEAL

The present appeal has been filed by M/s. Khushi Associates,4,SF-1, 2<sup>nd</sup> floor, Jaymadi Shanti Smurti Complex, B/s Little Wings BRTS Bus Stand, Bopal, Ahmedabad – 380058 (hereinafter referred to as "the appellant") against Order-in-Original No. GST-06/D-VI/O&A/703/Khushi/AM/2022-23 dated 10.03.2023 (hereinafter referred to as "the impugned order") passed by the Assistant Commissioner, Central GST and C. Ex., Division-VI, Ahmedabad North (hereinafter referred to as "the adjudicating authority").

2. Briefly stated, the facts of the case are that the appellant are holding PAN No. AAOFK8926F. On scrutiny of the data received from the Central Board of Direct Taxes (CBDT) for the FY 2016-17, it was noticed that the appellant had earned an income of Rs. 39,22,937/- during the FY 2016-17, which was reflected under the heads "Gross Receipts from Services (Value from ITR)" filed with the Income Tax department. Details of the same are as under:

F.Y	Value as per ITR in Rs.	Service tax not paid in Rs.
2016-17	39,22,937/-	5,88,440/-
Total	39,22,937/-	5,88,440/-

Accordingly, it appeared that the appellant had earned the said substantial income by way of providing taxable services but has neither obtained Service Tax registration nor paid the applicable service tax thereon. The appellant was called upon to submit copies of relevant documents for assessment for the above said period. However, the appellant had not responded to the letters issued by the department till the SCN issued.

2.1 Subsequently, the appellant was issued Show Cause Notice No. GST-06/04-1520/Khushi/2021-22 dated 18.10.2021 demanding Service Tax amounting to Rs. 5,88,440/for the period FY 2015-16, under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994. The SCN also proposed recovery of interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 and imposition of penalties under Section 70, Section 77and Section 78 of the Finance Act, 1994.

2.2 The Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned OIO wherein the adjudicating authority confirmed the demand of Service Tax only amounting to Rs. 5,88,440/- under proviso to Sub-Section (1) of Section 73 of the Finance Act, 1994 along with Interest under Section 75 of the Finance Act, 1994 for the period from FY 2016-17. Further (i) Penalty of Rs. 5,88,440/- was also imposed on the appellant under Section 78 of the Finance Act, 1994; (ii) Penalty of Rs. 10,000/- was imposed on the appellant under Section 77 of the

4

Finance Act, 1994. and (iii) Penalty of Rs. 40,000/- was imposed on the appellant under Section 70 of the Finance Act, 1994.

3. Being aggrieved with the impugned order passed by the adjudicating authority, the appellant have preferred the present appeal, inter alia, on the following grounds:

 The appellant submitted that they were providing Medical Services and Health Care Services during the F.Y. - 2016-17. Mr. Mahesh kumar Babulal Makwana is a Partner of the Appellant Partnership Firm and he is M.B.B.S. - Doctor by Profession providing medical services. According to section 66B of mega exemption notification no. 25/2012, Health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para - medics are included in mega exemption and this taxable service is exempt from whole of the service tax. Therefore, they had not taken Registration for Service Tax. They requested to set aside the impugned OIO and allow their appeal.

4. Personal hearing in the case was held on 06.02.2024.Shri Harish H. Patel & Dr. Mahesh (partner in Khushi Associates) appeared for the personal hearing on behalf of the appellant. They stated that the appellant is engaged in providing health services which is exempted. Hence no service tax liability is upon them.

5. I have carefully gone through the facts of the case, grounds of appeal, submissions made in the Appeal Memorandum, during the course of personal hearing and documents available on record. The issue to be decided in the present appeal is whether the impugned order passed by the adjudicating authority, confirming the demand of service tax against the appellant along with interest and penalty, in the facts and circumstance of the case, is legal and proper or otherwise. The demand pertains to the period FY 2016-17.

6. I find that in the SCN in question, the demand has been raised on the basis of the Income Tax Returns filed by the appellant as the appellant failed to reply of the departmental letters in time. Further they filed their reply against the SCN before the adjudicating authority, Therefore, the adjudicating authority adjudicated the matter ex-parte basis.

7. Now, as per the submission filed before me, It is observed that the appellant is a partnership firm which provides occupational health consultancy. I have gone through the sample invoices wherein the doctor visiting charge have been mentioned. Hence it is seen that the appellant is engaged in providing health care services which is exempted under Sr. No 2(i) of the Notification No. 25/2012-S.T. dated 20.06.2012. the relevant portion is reproduced as under:

Notification No. 25/2012-Service Tax New Delhi , the 20 th June, 2012

G.S.R.....(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)(hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of notification number 12/2012- Service Tax, dated the 17 thMarch, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 210 (E),dated the 17 th March, 2012, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, herebyexempts the following taxable services from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act,namely:-

1. .....;

2. Health care services by a clinical establishment, an authorised medical practitioner or para-medics; 3. .....;

8. In view of the above discussion, I am of the considered view that the activity carried out by the appellant during the FY 2016-17 are exempted from Service Tax as per 25/2012-S.T. dated 20.06.2012 and the appellant are not liable to pay service tax. Since the demand of Service Tax is not sustainable on merits, there does not arise any question of charging interest or imposing penalties in the case.

9. In view of above, I hold that the impugned order passed by the adjudicating authority confirming demand of Service Tax, in respect of income received by the appellant during the FY 2016-17, is not legal and proper and deserve to be set aside.

10. Accordingly, I set aside the impugned order and allow the appeal filed by the appellant.

Attested

Manish Kumar Superintendent(Appeals), CGST, Ahmedabad

## By RPAD / SPEED POST

To, M/s. Khushi Associates, 4,SF-1, 2<sup>nd</sup> floor, Jaymadi Shanti Smurti Complex, B/s Little Wings BRTS Bus Stand, Bopal, Ahmedabad – 380058

Appellant

आयुक्त (अपील्स)

0

Date

Respondent

The Assistant Commissioner, CGST & C. Ex., Division-VI, Ahmedabad North

Copy to :

The Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone
The Commissioner, CGST, Ahmedabad North
The Assistant Commissioner, CGST, Division VI, Ahmedabad North



6

4) The Assistant Commissioner (HQ System), CGST, Ahmedabad North (for uploading the OIA)

:/-;/-



